

था ताकि, वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण मदों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2014-15 से लागू करने के लिए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तुलन-पत्रों का एकीकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना पर निर्भर है, इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। लाभ और हानि लेखा के प्रारूप में संशोधन के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 के नियम 22 में संशोधन किया जाए। अतः, संशोधित तुलन-पत्र को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद और संशोधित नियमों को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अधिसूचित किए जाने के बाद वर्ष 2014-15 में इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

XII.4 तकनीकी समिति-II की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं,
 (क) रूपए में अंकित प्रतिभूतियों का पुनःमूल्यांकन करने की विधि

को लेखा और बाजार मूल्य में जो भी कम हो (एलओबीओएम) से परिवर्तित करते हुए उनका उचित मूल्यांकन करना और (ख) विदेशी विनियम वायदा करारों को लेखों में शामिल करना। सिफारिशों में विविध प्रकार के जोखिमों और भविष्य में रूपए की विनियम कीमत में वृद्धि होने, भविष्य में स्वर्ण के बाजार मूल्यों तथा विदेशी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की बाजार कीमत में कमी आने, परिचालनगत एवं प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए अपेक्षित बफर बनाने, आगे पूँजीगत व्यय करने तथा अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों में निवेश करने के लिए अपेक्षित बफर बनाने पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार को अधिशेष अंतरित करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति की रूपरेखा भी सिफारिशों में शामिल की गई है।

XII.5 वर्ष 2013-14 के लिए तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि खाता नीचे दिए जा रहे हैं।

30 जून 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ‘‘बैंक नोटों के निर्गम को नियन्त्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।’’

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- ए) बैंक नोटों का निर्गम।
- बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध करना।
- सी) बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।
- ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।
- जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।
- आइ) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।
- जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन,

विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

I. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

II. राजस्व निर्धारण

लाभांश को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है उसकी गणना प्राप्ति-आधार पर की जाती है और उगाही के निश्चित होने पर ही दंडात्मक ब्याज की गणना की जाती है। सिर्फ उगाहे गए लाभ को ही गणना में लिया जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कठिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

IV. रुपया प्रतिभूतियां

खजाना बिलों को छोड़कर, निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य (एलओबीओएम) पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्रचलित आय-ब्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में कमी का समायोजन, यदि कोई हो, चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

पुनर्खरीद करार (रिपो) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत संपर्किवक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों को अंकित मूल्य पर रिजर्व बैंक की बहियों में दर्शाया जाता है।

V. शेयर

शेयर में किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

VI. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि के संबंध में विवरण सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर/परिशोधन
पट्टधारित भूमि और उस पर बने भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किन्तु 5 प्रतिशत से कम नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) भूमि पर बने भवन	10 प्रतिशत

पट्टधारित भूमि पर परिशोधन प्रीमियम और भवनों पर मूल्यहास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

₹1,00,000/- से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित लाभ/हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

₹10,000 से अधिक लागत वाले मूल्यवान लेकिन आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि को पूंजीकृत किया गया है।

₹ 1,00,000 और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर की गयी है। अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास लगाया गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

‘अनुमानित इकाई ऋण’ प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

तैयार करने का आधार

XII.6 रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किए जाते हैं। वर्तमान परंपरा के अनुसार रिजर्व बैंक दो तुलन पत्र तैयार करता है। एक निर्गम विभाग के लिए, जिसका संबंध सिर्फ उसकी मुद्रा प्रबंध की जिम्मेदारी से होता है और दूसरा बैंकिंग विभाग के लिए जिसमें रिजर्व बैंक के अन्य सभी कार्यों का प्रभाव दर्शाया जाता है।

निर्गम विभाग की देयताएं तथा आस्तियां

निर्गम विभाग - देयताएं

XII.7 निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 34(1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिजर्व

प्रकार से 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि की शेष राशि ₹230 मिलियन रही।

iv) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए ₹500 मिलियन की प्रारंभिक पूँजी के साथ जनवरी 1989 में स्थापित निधि को उसके बाद से रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वार्षिक सहयोग के माध्यम से बढ़ाया गया है। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष लाभ-हानि (आय विवरण) से सिर्फ ₹10 मिलियन की टोकन राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹1,970 मिलियन की राशि जमा है।

v) अन्य निधियों में अंशदान

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 46ए के अधीन दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जिसके के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक के लिए ₹10 मिलियन का टोकन अंशदान राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में जमा किया जाता है।

vi) जमाराशियां

इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) और नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधियों संबंधी विविध खातों की शेष राशियों और हाल ही में स्थापित जमाकर्ता, शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की रिजर्व बैंक में रखी जाने वाली नकदी होती है। वर्ष के दौरान इस निधि का सृजन जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि करने के लिए और इस प्रकार के उद्देश्य जिन्हें समय-समय पर रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, के अनुसार जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, के लिए किया गया है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में ₹27.95

बिलियन की जमाराशि थी। कुल जमाराशि 30 जून 2013 के ₹3,738.92 बिलियन कुल राशि की तुलना में 30 जून 2014 को ₹3,892.54 बिलियन राशि रही जो 4.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

- जमाराशियां - सरकारी

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर केंद्र और राज्य सरकारों की जमा राशियों का अंतिम शेष क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.42 बिलियन था जिनका योग ₹1.42 बिलियन होता है जो पिछले वर्ष की समाप्ति के स्तर से लगभग बराबर ही रहा।

- जमाराशियां - बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक में बनाए रखे गए अपने चालू खाते में बैंक राशि नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भुगतान और निपटान के दायित्वों तथा आवश्यक कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा रखते हैं। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान 3.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल जमा राशि ₹3,677.24 बिलियन थी जबकि 30 जून 2013 को यह राशि ₹3,571.51 बिलियन थी।

- जमाराशियां - अन्य

2013-14 के दौरान अन्य जमाराशियों में समग्र रूप से 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें संचित सेवानिवृत्ति लाभों और हाल ही स्थापित डीईए निधि का प्रमुख योगदान रहा। विस्तृत विवरण सारणी XII.2 में दिया गया है।

vii) देय बिल

रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्वयं की भुगतान संबंधी आवश्यकता को मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इकलेक्ट्रॉनिक

सारणी XII.2: जमाराशियां - अन्य

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2013	2014
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	15.33	11.56
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	0.70	2.53
III. प्यूछुअल फंडों की जमाराशियां	0.02	0.01
IV. संचित सेवानिवृत्ति-अधिवर्षिता लाभ (i+ii)	141.02	161.72
(i) भविष्य निधि	36.10	38.62
(ii) ग्रेच्युइटी और सेवानिवृत्ति-निधि	104.92	123.10
V. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि	0.00	27.95
VI. विविध	8.90	10.11
कुल	165.97	213.88

भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) जारी करके पूरा भी करता करता है। इस मद की शेष राशि धन-प्रेषण समाशोधन खाते में धारित तत्कालीन धन-प्रेषण सुविधा योजना, 1975 के तहत के धन-प्रेषण और भुगतान गए मांग ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों को दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2013 के ₹1.87 बिलियन से घटकर 30 जून 2014 को ₹0.37 बिलियन रह गई जिसका मुख्य कारण डीडी/पीओ के जरिए धन-प्रेषण में कमी होना है जो भुगतान के इलेक्ट्रानिक प्रकार की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

viii) अन्य देयताएं

अन्य देयताओं में आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। जहां, आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) बैंक से प्राप्त लाभ से सृजित की जाती है, वहीं 'अन्य देयताओं' के शेष घटक जैसे कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) इत्यादि अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। अन्य देयताएं 30 जून 2013 के ₹8,082.86 बिलियन से 9.3 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2014 को ₹8,838.23 बिलियन हो गई जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में हुई वृद्धि होना था (सारणी XII.3)।

ए) आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर)

यह निधि अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दी गई कोई विशेष उत्तरदायित्व के चलते पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं।

बी) आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर)

1997-98 में सृजित आस्ति विकास आरक्षित निधि आंतरिक पूंजीगत खर्चों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थानों में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाभ में से उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है।

आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि का अंतरण

आंतरिक अध्ययन दल (अध्यक्ष : श्री वी. सुब्रह्मण्यम) (1997) की सिफारिशों के आधार पर आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि का लक्ष्य कुल आस्तियों का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था किंतु 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास निधि (एडीआर) दोनों मिलकर रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों का 9.2 प्रतिशत रहीं। पिछले पांच वर्षों के अंत की स्थिति सारणी XII.4 में

राशि कुल अधिशेष (चार निधियों में अंतरित करने से पहले) का 99.99 प्रतिशत है जबकि 2011-12 और 2012-13 में यह राशि क्रमशः 37.2 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत थी (सारणी XII.6)। इसमें पिछले वर्षों के समान, स्व-मूल्यांकन के आधार पर माइक्रो चेक प्रोसेसिंग शुल्कों के कारण देय अनुमानित सेवा कर के लिए ₹0.03 बिलियन की राशि और पिछले वर्ष के ₹13.22 बिलियन की तुलना में विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार को देय ब्याज-अंतर के रूप में ₹12.69 बिलियन की राशि भी शामिल है।

(एच) विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें छुट्टी का नकदीकरण किए जाने पर देय राशि, प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए आरक्षित निधि जिसे कर्मचारी निधियों के लिए अलग रखा गया हो, रिपो लेनदेनों के मार्जिन के रूप में धारित संपादिकीकृत निधि का मूल्य, कर्मचारियों के लिए चिकित्सकीय प्रावधानों इत्यादि जैसे उप लेखों को शामिल किया जाता है। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार विविध देयताएं ₹68.24 बिलियन रहीं जबकि 30 जून 2013 को ये देयताएं ₹67.23 बिलियन थीं।

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XII.9 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, विदेशों में धारित राशि, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलन पत्र में उनको चलनिधि के घटते क्रम में दर्शाया जाता है।

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों का स्टॉक होता है। इस स्टॉक के मूल्य में 37.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 30 जून 2013 के ₹ 0.08 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2014 को ₹ 0.11 बिलियन हो गया।

ii) खरीदे गए और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किंतु 2013-14 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iii) विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) एवं विदेशी मुद्रा रिजर्व (एफईआर)

बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) को तुलन पत्र में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पेश किया गया है: (क) विदेशी मुद्रा के रूप में विदेश में धारित शेष, जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दर्शाया गया है। (ख) बैंकिंग विभाग के निवेश के हिस्से के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां (इसमें जमाराशियां, ट्रेजरी-बिल, दिनांकित प्रतिभूतियां तथा बीआईएस/स्विफ्ट के शेयर शामिल हैं) एवं (ग) “निर्गम विभाग की आस्तियां” से संबंधित पैराग्राफ में उल्लेख किए गए अनुसार निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां (इसमें जमाराशियां, ट्रेजरी-बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं)।

विदेश में धारित शेष इस प्रकार हैं (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां, (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियां, (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी ट्रेजरी बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा, (v) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उपयोग किए गए विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)। पिछले दो वर्षों से संबंधित रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है।

विदेशी मुद्रा रिजर्व (एफईआर) में एफसीए, सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआरज) एवं रिजर्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं, जिनमें एफसीए का सर्वाधिक हिस्सा है। आईएमएफ की रिजर्व ट्रान्च स्थिति बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत सरकार के पास उसका शेयर

सारणी XII.8: बैंकिंग विभाग का निवेश

(₹ बिलियन)

निवेश	2012-13	2013-14
1	2	3
क) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां @	6,739.33	6,684.68
ख) विदेशी प्रतिभूतियां	520.90	1,066.69
ग) बीआईएस और स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) में शेयर	2.67	2.76
घ) सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं	13.20	13.20
कुल	7,276.10	7,767.33

@: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए ₹. 454.02 तथा 2013-14 के लिए ₹452.65 बिलियन के तेल बान्ड के रूप में जारी बान्ड शामिल है।

iv) निवेश

बैंकिंग विभाग के निवेश सारणी XII.8 में दिए गए

- ए. रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां 2012-13 के ₹ 6,739.33 बिलियन से घटकर 2013-14 में ₹ 6,684.68 बिलियन रह गई। पोर्टफोलियो की कुल रुपया प्रतिभूतियां वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ कम ही गई क्योंकि रीडेम्पशन (₹236.38 बिलियन का) एवं भारत सरकार के शेष में परिवर्तन (₹ 182.85 बिलियन का) ओएमओ (₹ 302.83 बिलियन का) के जरिए की गई खरीद से अधिक था। स्वयं रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की राशि ₹ 5,663.32 बिलियन थी; पुनःक्रय करार - रिपो के अंतर्गत प्राप्त संपार्शिकों की राशि ₹ 951.42 बिलियन थी जबकि सीमांत स्थायी सुविधा - एमएसएफ से संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ 92.46 बिलियन था और इसमें से रिवर्स रिपो खरीद के लिए संपार्शिक के रूप में प्रदत्त ₹ 22.52 बिलियन की प्रतिभूतियों को समायोजित किया गया है।

सारणी XII.9: सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं

(राशि ₹ मिलियन में)

1	लागत	% धारिता
	2	3
(क) निष्केप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	500.00	100.0
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	200.00	1.0
(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4,500.00	100.0
(घ) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8,000.00	100.0
कुल	13,200.00	-

सारणी XII.11: सकल आय

(₹ बिलियन)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
ए. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	251.02	211.5	198.10	207.46	197.68
बी. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	66.47	150.32	323.39	523.06	435.38
(ii) अन्य अर्जन	11.35	8.88	10.27	13.05	13.11
कुल: (i) + (ii)	77.82	159.20	333.66	536.11	448.49
सी. सकल आय (ए+बी)	328.84	370.70	531.76	743.58	646.17
डी. आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंतरण	51.68	121.67	246.77	262.47	0
ई. आस्ति विकास आरक्षित निधि में अंतरण	5.50	12.35	23.48	25.47	0
एफ. कुल आय (सी-डी-ई)	271.66	236.68	261.51	455.64	646.17

गई वायदा संविदा के मामले में इस खाते में दर्ज एमटीएम लाभों को अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाना चाहिए। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार खाता शेष ₹42.85 बिलियन था। 'अन्य आस्तियों' का मूल्य ₹ 854.56 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2014 को ₹ 933.37 बिलियन हो गया जो मुख्य रूप से निष्क्रिय बाजार स्वैप के परिशोधन तथा उक्त पैराग्राफ में बताए गए अनुसार वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन के बाद हुए एमटीएम लाभों के कारण है।

आय एवं व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 रिजर्व बैंक को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है- (i) ब्याज प्राप्तियां, (ii) डिस्काउंट, (iii) विनिमय, (iv) कमीशन तथा (v) अन्य आय जिनमें प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा जरूरत महसूस न किए गए प्रावधान। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहता है। सकल आय तथा देशी और विदेशी स्रोतों से पिछले 5 वर्षों में हुए अर्जन का व्यौरा सारणी XII.11 में दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XII.11 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में मुख्यतः विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। यह आय 2012-13 के ₹ 207.46 से ₹ 9.78 बिलियन (4.7 प्रतिशत) घटकर 2013-14 में ₹ 197.68 बिलियन रह गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2012-13 के 1.45 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में कम अर्थात् 1.21 प्रतिशत रही जो वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज की दर कम रहने की वजह से है (सारणी XII.12)।

सारणी XII.12 : विदेशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष			घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014		पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	15,247.68	17,579.52	2,331.84	15.29	
ओसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	14281.58	16,368.93	2,087.35	14.62	
विदेशी मुद्रा आस्तियां से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूँजीगत लाभ/हानि)*	207.46	197.68	(-) 9.78	(-) 4.71	
ओसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के रूप में एफसीए से अर्जन	1.45	1.21	-	-	

* वर्ष 2013-14 के दौरान आय में स्वैप प्रेमियम की ₹ 59.30 बिलियन राशि शामिल हैं।

देशी स्रोतों से आय

XII.12 देशी स्रोतों से निवल आय 2012-13 के ₹536.11 बिलियन की तुलना में 2013-14 में 16.3 प्रतिशत घटकर ₹448.49 बिलियन रह गई। देशी आय की विभिन्न मर्दों का विस्तृत व्यौरा सारणी XII.13 में दिया गया है। रुपया प्रतिभूतियों के कुल धारण में कमी (सारणी XII.8) के बावजूद कूपन प्राप्तियों से आय 2013-14 के ₹470.53 बिलियन की तुलना में 2012-13 में बढ़कर ₹408.68 बिलियन हो गई क्योंकि वर्ष में ₹302.83 बिलियन की सरकारी प्रतिभूति की खरीद की गई। तथापि, समग्र गिरावट मुख्यतया, रुपया प्रतिभूतियों पर हास में 2012-13 के ₹55.38 बिलियन की तुलना में 2013-14 में ₹480.45 बिलियन की वृद्धि (क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2013-14 में मुनाफा सामान्यतः दृढ़ हो गया था) के कारण आई।

XII.13 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से निवल व्याज आय 2012-13

के ₹64.90 बिलियन से बढ़कर 2013-14 में ₹76.77 बिलियन हो गई जिसके प्रमुख कारण हैं (i) जुलाई 2013 में 200 आधार अंक से एमएसएफ दर में वृद्धि और (ii) एलएफ उधार का एक महत्वपूर्ण भाग वर्तमान रिपो दर से उच्चतर दरों पर मीयादी रिपो व्यवस्था के माध्यम से दिया जाना।

XII.14 जुलाई 2013-जून 2014 की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट (डब्ल्यूएमए/ओडी) के प्रति केन्द्र से प्राप्त व्याज आय 2012-13 के दौरान उसी अवधि के लिए ₹0.67 बिलियन की तुलना में बढ़कर ₹3.22 बिलियन हो गयी। पिछले वर्ष के 27 दिनों के अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने और कोई ओवरड्राफ्ट न लिये जाने की तुलना में केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान 52 दिन अर्थोपाय अग्रिमों तथा 10 दिनों का ओवरड्राफ्ट लिये जाने के कारण केन्द्र द्वारा 2013-14 में डब्ल्यूएमए/ओडी का मासिक औसत उपयोग ₹299.4 बिलियन था जबकि 2012-13 में यह ₹98.1 बिलियन था।

सारणी XII.13 : देशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2013	30 जून 2014	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	8,659.35	8,664.04	4.65	0.05
देशी आस्तियों का सापाहिक औसत अर्जन (I + II+III)	7,724.84 536.11	8,694.77 448.49	969.95 (-)87.62	12.56 (-)16.34
I. व्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	85.47	331.37	245.90	287.70
ii) एलएफ परिचालनों पर निवल व्याज	64.79	59.02	(-)5.77	(-)8.90
iii) एमएसएफ परिचालनों पर व्याज	0.11	17.45	17.34	15763.64
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर व्याज	408.68	470.53	61.85	15.13
v) मूल्यहास	55.38	480.45	425.07	767.55
कुल (i+ii+iii+iv-v)	503.67	397.92	(-)105.75	(-)21.00
II. छूटों और अग्रिमों पर व्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	1.26	3.88	2.63	208.73
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	17.65	33.10	15.45	87.54
iii) कर्मचारियों को	0.48	0.48	0.00	0.0
कुल (i+ii+iii)	19.39	37.46	18.07	93.19
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.28	0.01	(-)0.27	(-)96.43
ii) विनिमय	-	-	-	-
iii) कमीशन	11.13	12.57	1.44	12.94
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	1.64	0.53	(-)1.12	(-)68.29
कुल (i+ii+iii+iv)	13.04	13.11	0.06	0.46

2013-14 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

बैंकों का अदा किया गया एजेंसी कमीशन

रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये शाखाएं सरकारी फुटकर लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। रिजर्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया है। सरकारी लेन-देन करने के लिए इन बैंकों को वर्ष 2013-14 में 27.81 बिलियन रुपये कमीशन अदा किया गया जो, इसकी तुलना में वर्ष 2012-13 में 27.26 बिलियन रुपये था, अर्थात् इसमें 2.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे ज्ञात होता है कि सरकारी कारोबार की मात्रा बढ़ गई है।

प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को अदा किया गया हामीदारी कमीशन शुल्क

हामीदारी कमीशन पर व्यय अत्यधिक बढ़ गया क्योंकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिक व्यापारियों ने हामीदारी कमीशन की ऊंची दरें उद्धृत की थीं।

बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे से हिस्से के

प्रबंधन का कार्य बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को सौंपा गया था जिसके लिए उन्हें 2013-14 में 0.63 बिलियन रुपये शुल्क अदा किया गया जो वर्ष 2012-13 में 0.58 बिलियन रुपये था।

बी) प्रतिभूति मुद्रण

प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (प्राथमिक रूप से करेंसी नोट के मुद्रण के लिए) पर हुए व्यय में 11.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 के 28.72 बिलियन रुपये से बढ़कर 2013-14 में 32.14 बिलियन रुपये हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंक नोट फार्मों की कुल आपूर्ति में 15.14 प्रतिशत की वृद्धि तथा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल) द्वारा करेंसी नोटों की आपूर्ति के लिए थोड़ी सी बढ़ी हुई दर उद्धृत करने के फलस्वरूप हुई।

सी) अन्य

अन्य स्थापना से इतर व्यय जैसे खजाना के प्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा-परीक्षा, शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं जिसमें वृद्धि 10.08 बिलियन रुपये से बढ़कर 10.67 बिलियन रुपये हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय

सारणी XII.16: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

मद		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
		2	3	4	5	6
1						
ए) सकल आय		328.84	370.70	531.76	743.58	646.17
बी) आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)		57.18	134.02	270.25	287.94	0.00
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि		51.68	121.67	246.77	262.47	0.00
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि		5.50	12.35	23.48	25.47	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)		271.66	236.68	261.51	455.63	646.17
डी) कुल व्यय		84.03	86.55	101.37	125.49	119.34
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)		187.63	150.13	160.14	330.14	526.83
एफ) निधियों में अंतरण*		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)		187.59	150.09	160.10	330.10	526.79
सकल आय में कुल व्यय घटाकर प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण		76.6	52.8	37.2	53.4	99.99

* : पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

तथा सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय, संगामी लेखा परीक्षा तथा बैंक में विभिन्न प्रयोजनों से की गई विशेष लेखापरीक्षा संबंधी व्यय पर ₹24.22 मिलियन अदा किए गए। विविध व्यय में विभिन्न अकादमी प्रशिक्षण संस्थान आदि को दिए गए अंशदान शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय प्रवृत्ति XII.16 में दी गई है (पिछले वर्ष के आंकड़ों का, आवश्यकतानुसार समूहन/वर्गीकरण पुनः किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप हो सके)।

लेखा-परीक्षक

बैंक के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2013-14 के लेखा की लेखा-परीक्षा मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई और मैसर्स सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षक के रूप में और मैसर्स एस.के. मेहता एंड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स पी.के. एफ. श्रीधर एंड संतनम एंड कंपनी, चेन्नै तथा मैसर्स लोढा एंड कं., कोलकता द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में की गई।